<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>

फ्यूचर एनर्जी एशिया 2023: इरेडा के सीएमडी ने सीईओ राउंड टेबल पर प्रोएक्टिव कार्बन कैप्चर स्टोरेज और सीक्वेस्ट्रेशन का आग्रह किया

बैंकॉक, थाईलैंड, 19 मई, 2023

भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था (इरेडा) के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, श्री प्रदीप कुमार दास ने श्री प्रदीप कुमार दास, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक ने कल एशिया नेचुरल गैस एंड एनर्जी एसोसिएशन द्वारा प्रायोजित फ्यूचर एनर्जी एशिया(एफईए) 2023, में सीईओ राउंड टेबल में पारंपरिक स्रोतों से कम से कम उत्पादन और विद्युत के कम उपयोग करके कार्बन उत्सर्जन से बचने की आवश्यकता को सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया।

श्री दास ने इस बात पर प्रकाश डाला कि नवीकरणीय ऊर्जा (आरई) क्षेत्र में भारत की उल्लेखनीय प्रगति विश्व औसत विकास दर को पार कर गई है, और इस उपलब्धि में इरेडा का प्रमुख योगदान रहा है। उन्होंने आगे कहा कि जबकि भारत दुनिया में सबसे बड़ी आबादी वाला देश बन गया है,किंतु भारत में प्रति व्यक्ति की ऊर्जा की खपत और प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन की तीव्रता दुनिया के औसत और अन्य विकसित देशों की तुलना में काफी कम है।

उन्होंने जोर देकर कहा कि जबकि भारत ने समय से पहले ही गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों से बिजली उत्पादन के 40% हिस्से के अपने पहले के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है और भारत सरकार ने वर्ष 2030 तक उत्सर्जन में कमी के लिए लक्ष्यों, योजनाओं और नीतियों को पहले ही अधिसूचित कर दिया है।

उन्होंने आगे कहा कि भारत अब 2005 के स्तर से 2030 तक अपने जीडीपी की उत्सर्जन तीव्रता को 45 प्रतिशत तक कम करने के लिए प्रतिबद्ध है और वर्ष 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा संसाधनों से लगभग 50 प्रतिशत संचयी विद्युत ऊर्जा स्थापित क्षमता हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध है।

जबकि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) का उद्देश्य सौर ऊर्जा समाधानों की इष्टतम और नियोजित विस्तार के माध्यम से जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध प्रयासों को गति देना है और भारत सक्रिय रूप से भूटान, नेपाल, म्यांमार और बांग्लादेश जैसे अन्य एशियाई देशों के साथ आरई लेन-देन के बारे में चर्चा कर रहा है, जिसमें आरई विकास और उपलब्ध संसाधनों और ऊर्जा खपत के इष्टतम उपयोग को आगे बढ़ाने के लिए कई समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर भी शामिल हैं।

श्री दास ने इस बात पर प्रकाश डाला कि भारत की स्थापित गैर-जीवाश्म ईंधन क्षमता पिछले 8.5 वर्षों में 396% बढ़ी है, जबकि स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता पिछले 9 वर्षों में 24.4 गुना बढ़ी है। उन्होंने कहा कि भारत के माननीय प्रधान मंत्री द्वारा **वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड** पहल के अनुरूप, वैश्विक स्तर पर कार्बन कैप्चर स्टोरेज एण्ड सेक्रस्ट्रैशन (सीसीएसएस) के इष्टतम निष्पादन और उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए संपूर्ण मूल्य श्रृंखला में सभी स्तरों पर समयबद्ध और समग्र प्रयासों की आवश्यकता है।

उन्होंने जोर देकर कहा कि इष्टतम सीसीएसएस सुनिश्चित करने के लिए, देश के प्रत्येक बिजली उपभोक्ता/नागरिक के लिए एक व्यापक जागरूकता कार्यक्रम की आवश्यकता है, साथ ही संपूर्ण मूल्य श्रृंखला में हितधारकों की समय पर इष्टतम क्षमता निर्माण की आवश्यकता है। उन्होंने आगे कहा कि प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सही समय पर और सही तरीके से सही नीति स्थापित करने से निश्चित रूप से सीसीएसएस के दिशा में सर्वोत्तम प्रत्याशित परिणाम प्राप्त होंगे।

इस राउंड टेबल में ऊर्जा मंत्रालय, थाईलैंड साम्राज्य के वरिष्ठ प्रतिनिधियों, सीईओ और ऊर्जा क्षेत्र के विभिन्न अंतरराष्ट्रीय संगठनों के प्रमुखों ने भाग लिया। इस विचार-विमर्श में कार्बन कैप्चर की उच्च लागत सहित सीसीयूएस परियोजनाओं के लिए सामना की जा रही आर्थिक और परिचालन चुनौतियों का वित्तपोषण शामिल था।